अजय कुमार परमार

बनाम

राजस्थान राज्य

(2012 की आपराधिक अपील संख्या 1496)

27 सितंबर, 2012

[डॉ. बी. एस. चौहान और फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस।207 209 और एस।164 - मजिस्ट्रेट की शक्ति बलात्कार का आरोप लगाने वाली एफ. आई. आर.-इसके बाद अभियोजक ने अपना बयान दर्ज प्राथमिकीने के लिए खुद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी. जे. एम.) से संपर्क किया।164 Cr.P.C-सी. जे. एम. के आदेश के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट उसका बयान दर्ज करता है।164 - अभियोजक ने अपने बयान में कहा।164 अभियोजक उल के बयान को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को आरोपों से बरी करना-पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दायर करना-न्यायिक मजिस्ट्रेट।164, अभियुक्त को आरोपमुक्त करना-पुनरीक्षण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया मजिस्ट्रेट का आदेश-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःमजिस्ट्रेट के आदेश को सही ढंग से दरकिनार कर दिया गया है-बयान यू/एस।164 सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया था।ई अभियोजक को पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया था और यह कि उसका बयान उसकी पहचान किए बिना दर्ज किया गया था-आरोपमुक्त करने का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना अमान्य था क्योंकि मामला सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञेय था-मजिस्ट्रेट को मामले की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था-वह कानून के तहत मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने के लिए बाध्य था-उस स्तर पर साक्ष्य के भार की जांच करने की भी अनुमति नहीं थी-सीजेएम और न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कागजात पर अभियोजक के हस्ताक्षर भी प्राथमिकी और चिकित्सा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर के साथ मेल

नहीं खाते थे जो संदेह पैदा करते हैं।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -धारा 73-हस्ताक्षर की तुलना!अदालत द्वारा लिखा गया-आयोजितःअदालत को इस तरह की तुलना करने से रोकने के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है-लेकिन विवेक और सावधानी के मामले में अदालत को अपने निष्कर्षों को पूरी तरह से उसके द्वारा की गई तुलना पर आधारित करने में देरी करनी चाहिए-अदालत अपने अवलोकन को विशेषज्ञ की राय या किसी अन्य गवाह की राय पर लागू कर सकती है।

अपीलार्थी-अभियुक्त के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।अभियोजक, इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ और एक शिकायत दर्ज की जिसमें कहा गया कि पुलिस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही थी और एक आवेदन दायर किया कि उसका बयान दर्ज किया जाए। 164 Cr.P.C. आवेदन की अनुमति दी गई थी।नतीजतन, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियोजक उल का बयान दर्ज किया। 164 Cr.P.C. इस प्रभाव लिए किउसके द्वारा दर्ज प्राथमिकीाई गई एफ़. आई. आर. झूठी थी; कि उसका बयान गलत था।161 Cr.P.C. भी गलत था और अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा कभी कोई अपराध नहीं किया गया था।

जाँच के समापन पर, पुलिस ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट, बयान ध्यान दें में रखते हुए।164 Cr.P.C., ने अपराधों का संज्ञान नहीं लेने का आदेश पारित किया।376 और 342 भा.दं.सं. सी. और अपीलार्थी-अभियुक्त को आरोपमुक्त कर दिया।राज्य ने पुनरीक्षण दायर किया और सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के आदेश को उलटते हुए इसकी अनुमति दी।सत्र न्यायालय के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी इसलिए वर्तमान अपील।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1.पुनरीक्षण अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि

खंड 164 Cr.P.C के तहत बयान सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया था।उक्त अदालतों ने अपराध का संज्ञान नहीं लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया है।एक कथन यू/एस।164(5) Cr.P.C. को केवल और केवल तभी दर्ज किया जा सकता है जब इस तरह का बयान देने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है।ऐसी कार्रवाई के मामले में, जिसमें ऐसे व्यक्ति को अपनी इच्छा से मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की अनुमति दी जाती है, अनुमति दी जाती है, और अदालत के दरवाजे उनके लिए खुले होते हैं कि वे अपनी इच्छानुसार आएं, और यदि मजिस्ट्रेट उनके सभी मामलों को दर्ज करना शुरू कर देता बयानों के बाद, उक्त दोषियों की सहायता के लिए अग्रिम रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से, दोषियों द्वारा प्रायोजित बहुत से व्यक्ति मजिस्ट्रेट अदालतों के पोर्टल के सामने जमा हो सकते हैं।[पैरा 5] [982-8-0]

जोगेंद्र नाहक और अन्य. बनाम उड़ीसा राज्य अन्य अन्य। ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 2565:1999 (1) पूरक।एस. सी. आर. 39-पर निर्भर।

1.2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिन्होंने आवेदन पर विचार किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट को आगे प्रो. यू. टी. आर. एस. का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, मामले में अभियोजक को ज्ञात नहीं था और बाद वाले ने किसी भी अदालत के अधिकारी/वकील/पुलिस या किसी और द्वारा पहचान करने के प्रयास के बिना उसका बयान भी दर्ज किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर आवेदन पर अभियोजक के साथ-साथ उसके वकील ने भी हस्ताक्षर किए हैं।हालाँकि, अभियोजक की कोई पहचान नहीं की गई है, न तो उक्त अधिवक्ता द्वारा या किसी और द्वारा।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अभियोजक की पहचान किए बिना आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े और कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया कि वह अभियोजक को व्यक्तिगत रूप से जानता था।न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वकील द्वारा उसकी पहचान किए जाने के बाद अभियोजक का बयान दर्ज किया। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वह अपने माता-पिता या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति के साथ मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुई थी।ऐसी परिस्थितियों में, इस तरह से दर्ज किया गया बयान अपना महत्व और कानूनी पवित्रता खो देता है।तथ्य-स्थिति से पता चलता है कि अदालत बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ी और इतनी जल्दबाजी में की गई किसी भी कार्रवाई को मनमाना करार दिया जा सकता है।[पारस 7,16 और 17] [982-जी-एच; 986-जी-एच; 987-ए-8, डी-ई]

महाबीर . बनाम हरियाणा राज्य ए. आई. आर 2001 एस. सी. 250:2001 (1) पूरक एस. सी. आर. 37-पर निर्भर।

2.1.जब कोई अपराध सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञेय होता है, तो मजिस्ट्रेट मामले की जांच नहीं कर सकता है और आरोपी को आरोपमुक्त नहीं कर सकता है।अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद भी उसके लिए ऐसा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उसके पास मामले की जांच करने या देखने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार, मजिस्ट्रेट के पास अपीलकर्ता को आरोपमुक्त करने का कोई कार्य नहीं था।वह कानून के तहत मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने के लिए बाध्य था, जहां आरोपमुक्त करने के लिए इस तरह के आवेदन पर विचार किया जाएगा।इसलिए, निर्वहन का आदेश एक शून्यता है, जो अधिकार क्षेत्र के बिना है।[पारस 9 और 10] [983-जी-एच; 984-ए-डी]

संजय गांधी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 514:1978 (2) एस. सी. आर. 861-पर निर्भर।

2.2. न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, आरोप तैयार करने के समय अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव में साक्ष्य को ध्यान में रखना अनुज्ञेय नहीं था, केवल जिन दस्तावेजों पर विचार किया जाना आवश्यक है, वे आरोप-पत्र के साथ जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज हैं।जिस दस्तावेज पर आरोपी भरोसा करना चाहता है, उसे सबूत के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।यदि इस तरह के साक्ष्य पर विचार किया जाना है, तो आरोप तय करने के चरण में एक छोटा परीक्षण होगा। यह Cr.P.C के उद्देश्य को विफल कर

देगा। खंड 227 द्वारा अभिनिर्धारित अभियुक्त की प्रस्तुतियों को सुनने के प्रावधान का अर्थ है अभियोजन पक्ष द्वारा दायर मामले के रिकॉर्ड पर अभियुक्त की प्रस्तुतियों को सुनना और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और इससे अधिक कुछ नहीं।भले ही, एक दुर्लभ मामले में बचाव पक्ष के साक्ष्य पर विचार करने की अनुमति है, अगर ऐसी सामग्री आश्वस्त रूप से स्थापित करती है कि पूरा अभियोजन संस्करण पूरी तरह से हास्यास्पद तर्क, हास्यास्पद तर्क या मनगढ़ंत है, तो तत्काल मामला उस श्रेणी में नहीं आता है।[पैरा 11] [984-0-H]

उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाधी ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1512; उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाधी ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 359:2004 {6) पूरक।एससीआर 460; एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनामनीता भल्ला और अन्र। एआईआर 2005 एससी 3512:2005 (3) पूरक।एससीआर 371; भारत पारिख बनाम सी. बी. आई. और अन्र। (2008) 10 सी एससीसी 109:2008 (10) एस. सी. आर. 950; रुक्मिणी नार्वेकर अन्य विजया सतार्देकर और अन्य। आकाशवाणी 2009 एससी 1013:2008 (14) एस. सी. आर. 271-पर निर्भर।

2.3.अदालत को संज्ञान नहीं लेने के पाठ्यक्रम का सहारा लेकर दोषमुक्ति का आदेश पारित नहीं करना चाहिए, जहां प्रथमदृष्टया मामला जांच एजेंसी द्वारा बनाया जाता है।इसके अलावा, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह पीड़ित के अधिकार और हितों की रक्षा करे, जो अभियोग कार्यवाही में भाग नहीं लेता है।खंड 227 के आवेदन के चरण में, अदालत को यह पता लगाने के लिए साक्ष्य को स्थानांतरित आदेशना पड़ता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।इस प्रकार, इस स्तर पर साक्ष्य की सराहना की अनुमति नहीं है।[पैरा 12) [985-बी-0]

पी. विजयन बनाम केरा/ए और अन्र राज्य। आकाशवाणी 2010 एससी 663:2010(2) एससीआर 78; आर. एस. मिश्रा अन्य उड़ीसा राज्य और अन्य। ए.

आई. आर. 2011 एस. सी. 1103 2011 (2) एस. सी. आर. 338-पर निर्भर था।

2.4.Cr.P.C की योजना. विशेष रूप से, धारा 207 से 209 Cr.P.C के प्रावधान, मजिस्ट्रेट को आरोप-पत्र दायर होने पर मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने का आदेश देते हैं।इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस द्वारा स्थापित मामले में विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले का समर्पण अनिवार्य है।[पैरा 13) [985-एच 0-ई]

2.5.जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेने और कार्यवाही को छोड़ने का निर्णय लेता है या यह विचार रखता है कि प्राथमिकी में उल्लिखित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, सूचना देने वाले को नोटिस देना और मामले में सुनवाई की अनुमति देना अनिवार्य हो जाता है।हाथ में मामले में, स्वीकार्य रूप से, मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही को छोड़ने से पहले शिकायतकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया है और इस प्रकार, इसका उल्लंघन करते हुए कार्य किया है।कानून की अनिवार्य आवश्यकता।[पैरा 15) [986-ई-एफ]

मीनू कुमारी और अन्र. बनाम बिहार राज्य अन्य अन्य। ए. आई. आर 2006 एस. सी. 1937:2006 (3) एससीआर 1086; भगवंत 9. बनाम पुलिस आयुक्त और ए. एन. आर. AIR 1985 SC 1285:1985(3) एससीआर 942-प्रतिष्ठित।

3.1.एफ. आई. आर. और मेडिकल रिपोर्ट पर अभियोजक के हस्ताक्षरों की तुलना में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर आवेदन पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षरों के साथ, खंड 164 Cr.P.C के तहत उसका बयान दर्ज प्राथमिकीने के लिए, साथ ही, खंड 164 Cr.P.C के तहत उसके द्वारा कथित रूप से दिए गए बयान पर हस्ताक्षर के साथ, और उसी की जांच प्राथमिकीने के बाद, प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है कि वे एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं किए गए हैं, क्योंकि हस्ताक्षरों के दो सेट मेल नहीं खाते हैं, बल्कि उनके बीच एक स्पष्ट असमानता है।[पैरा 18) [987-ई-जी] एफ

3.2:एफ. आई. आर. और चिकित्सा रिपोर्ट पर प्रकृति से यह प्रतीत होता है कि वह एक शिक्षित व्यक्ति नहीं है और मुश्किल से अपने हस्ताक्षर प्राथमिकी सकती है।इस प्रकार, यह संदेह पैदा करता है कि कैसे एक 18 वर्षीय, जो एक अनपढ़ देहाती ग्रामीण है, अदालत में पहुंची और उसे कैसे पता था कि उसका बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जा सकता है। [पैरा 24) [990-G-H; 991-A]

3.3.भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की तीन धाराओं अर्थात धारा 45,47 और 73 द्वारा हस्ताक्षर की पहचान के साक्ष्य पर विचार किया गया है।साक्ष्य अधिनियम की खंड 73 में न्यायालय द्वारा अपनी उपस्थिति में दिए गए लिखित नमूने के साथ की गई तुलना का प्रावधान है, या स्वीकार किया गया है, या संबंधित व्यक्ति का लेखन साबित हुआ है। अदालत को हस्ताक्षर या लिखावट की तुलना करने से रोकने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है, विवादित लेखन की तुलना स्वीकृत लेखन से करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करके और फिर उक्त लिखावट को समान या अलग साबित करने के लिए अपने स्वयं के अवलोकन को लागू करने से, जैसा भी मामला हो, लेकिन ऐसा करने में, अदालत स्वयं इस संबंध में विशेषज्ञ नहीं बन सकती है और उसे एक विशेषज्ञ की भूमिका निभाने से बचना चाहिए, इस सरल कारण से कि अदालत की राय भी निर्णायक नहीं हो सकती है।इसलिए, जब अदालत इस तरह के कार्य को अपने ऊपर लेती है, और निष्कर्षों को केवल हस्ताक्षर या हस्तलेखन की तुलना के आधार पर दर्ज किया जाता है, तो अदालत को इसमें शामिल जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अदालत द्वारा बनाई गई राय निर्णायक नहीं हो सकती है और त्रुटि के लिए अतिसंवेदनशील है, विशेष रूप से जब अभ्यास किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो विषय से परिचित नहीं है।इसलिए, न्यायालय को विवेक और सावधानी के मामले में अपने निष्कर्षों को केवल उसके द्वारा की गई तुलना पर आधारित करने में संकोच या देरी करनी चाहिए। हालाँकि, जहाँ किसी विशेषज्ञ या किसी गवाह की राय है, वहाँ न्यायालय अपने निर्णय को निर्णायक महत्व या प्रभाव प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर,

या लिखावट की तुलना करके अपने अवलोकन को लागू कर सकता है।[पारस 19 और 23] (987-एच; 988-ए; 989-एफ-एच; 990-ए-बी)

रामचंद्र और अन्र. बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 381; ई. एस. मिश्रा बनाम मोहम्मद ईसा ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1728:1963 एससीआर 722; शशि कुमार बनर्जी और ओआरएस अन्यसुबोध कुमार बनर्जी ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 529; फखरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1326; महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह और अन्र। ए. आई. आर 1992 एस. सी. 2100:1992 (3) एस. सी. आर. 480; मुरारी लाल अन्य मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 363; नीललोहितदासन एच. नादर अन्य जॉर्ज मास्क्रीन और अन्य। 1994 सप.(2) एस. सी. सी. अजय कुमार परमार बनाम राजस्थान राज्य 977 619;0. भारतन अन्य के. सुधाकरन और अन्र। ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1140; ला/इट पोपली अन्य केनरा बैंक और अन्य। ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1795; जगजीत 9. अन्य हरियाणा राज्य और अन्य। (2006) 11 एससीसी 1:2006 (10) पूरक।एस. सी. आर. 521; तिरुवेंगाडा पिल्लई बनाम नवनीथम्मल ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 1541:2008 (3) एस. सी. आर. 23; सोमेश्वर राव बनाम समीनेनी नागेश्वर राव और अन्र। (2009) 14 एससीसी 677:2009 (11) एससीआर 676-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भः1999 (1) पूरक।एस. सी. आर. 39 2001 (1) सप्लीमेंट पर आधारित।एस. सी. आर. 37 पैरा 5 पारा 6 पारा 81978 (2) एस. सी. आर. 861 ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1512 पर भरोसा किया गया 2004 (6) पूरक पर भरोसा किया गया।एस. सी. आर. 460 2005 (3) सप्लीमेंट पर विश्वसनीय।एस. सी. आर. 371 पर 2008 को (10) एस. सी. आर. 950 पर 11 पैरा 2008 को (14) एस. सी. आर. 2712010 (2) एस. सी. आर. 782011 (2) एस. सी. आर. 3382006 (3) एस. सी. आर. 10861985 (3) एस. सी. आर. 942 ए. आई. आर. 1957 एस. सी.

3811963 एस. सी. आर. 722 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 529 ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 13261992 (3) एस. सी. आर. 480 ए. आई. आर. 191 एस. सी. 363(2) धारा 619 पैरा 21 ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1140 पैरा 22 ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1795 पैरा 222006 (10) सप्लीमेंट पर निर्भर है।एस. सी. आर. 521 पैरा 22,2008 (3) एस. सी. आर. 23 पैरा 22,2009 (11) एस. सी. आर. 676 पैरा 22 पर आधारित

आपराधिक अधिकार क्षेत्र न्यायनिर्णयः2012 की दाण्डिक अपीलीय सं 1496।

1998 के एस. बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सं. 458 में जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से ऐश्वर्या भाटी, ज्योति उपाध्याय।

प्रत्यर्थी के लिए इरशाद अहमद।

न्यायालय का निर्णय डॉ. बी. एस. चौहान, जे. द्वारा सुनाया गया

1. इस अपील को जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 1998 की एस. बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 458 में दिनांक 1 के विवादित निर्णय और आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है, जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय ने 1998 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 5 में सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 2 के निर्णय और आदेश को बरकरार रखा है।उक्त पुनरीक्षण आदेश के माध्यम से, अदालत ने अपीलकर्ता को धारा 376 और 342 के तहत अपराधों के लिए आरोपमुक्त करने के आदेश को उलट दिया था।डायन दंड संहिता, 1860 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) दिनांक 25.3.1998, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज द्वारा पारित।2.इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य और परिस्थितियाँ इस प्रकार हैंः

ए. अपीलकर्ता के खिलाफ 22.3.1997 पर एक प्राथमिकी आर. दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता ने 10.3.1997 पर उसके साथ बलात्कार किया था। इसे ध्यान में रखते हुए, एक जांच शुरू की गई और अपीलार्थी की चिकित्सकीय जांच की गई।इसके बाद अभियोजक के कपड़े भी बरामद किए गए और उन्हें एफएसएल रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा गया।अभियोजक की चिकित्सकीय जांच की गई, जिसमें डॉक्टर द्वारा यह राय दी गई थी कि वह यौन संभोग की आदी थी, हालांकि, रासायनिक परीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही नए संभोग के बारे में अंतिम राय दी जाएगी।

बी. अभियोजक का बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 161 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने प्राथमिकी में उल्लिखित घटना का वर्णन करते हुए कहा कि वह पिछले छह वर्षों से एक बहन दुर्गी के आवास पर एक नौकर के रूप में कार्यरत थी।बहन दुर्गी के आवास के पास डॉ. डी. आर. परमार और उनके बेटे अजय परमार भी रह रहे थे।उक्त घटना के दिन, अजय परमार ने अभियोजक पुष्प को इस बहाने घर बुलाया कि उसके लिए एक टेलीफोन कॉल आया था।जब वह अजय परमार के आवास पर पहुंची, तो उसके द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया और उसे लंबे समय तक बाहर जाने से रोक दिया गया और बिना किसी भोजन या पानी के घर के अंदर रखा गया। हालाँकि, अगली शाम, उसे उक्त घर के पिछले निकास द्वार से गुप्त रूप से बाहर धकेल दिया गया। फिर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की लेकिन प्रकाश सेन और विक्रम सेन ने उसे बचा लिया और फिर, अंततः, लगभग 10 दिनों के अंतराल के बाद, विचाराधीन शिकायत एसपी, एफ सिरोही को सौंप दी गई।इसके बाद, वह स्वयं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष 9.4.1997 पर पेश हुई और उसके समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि हालांकि उसने आई. पी. सी. की खंड 376/342 के तहत एक भा.दं.सं. दर्ज की थी, लेकिन पुलिस मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर रही थी और इसलिए, वह खंड 164 Cr.P.C के तहत अपना बयान देना

चाहती थी।

सी. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही ने उक्त आवेदन पर विचार किया और उसी दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज को खंड 164 Cr.P.C के तहत अपना बयान दर्ज करने का निर्देश देकर इसका निपटारा कर दिया।

डी. इसके अनुसरण में, अभियोजक न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज, जो सिरोही से बहुत दूर 8 पर है, के समक्ष 9.4.1997 पर ही पेश हुआ और सभी आवश्यक कागजात मजिस्ट्रेट को सौंप दिए।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही द्वारा पारित आदेश की जांच करने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज ने लोक अभियोजक को उसी दिन शाम 4 बजे मामले की केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया।

ई. चूंकि लोक अभियोजक शाम 4 बजे केस डायरी पेश नहीं कर सका, इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज ने लोक अभियोजक को 10.00 ए. एम. पूर्वाह्न 10.4.1997 पूर्वाह्न केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया।खंड 164 Cr.P.C के तहत अभियोजक का बयान वकील द्वारा पहचाने जाने के बाद दर्ज किया गया था, इस प्रभाव से कि उसके द्वारा दर्ज की गई उक्त प्राथमिकी झूठी थी; इसके अलावा, खंड 161 Cr.P.C के तहत उसके द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष दिया गया बयान भी गलत था; और अंत में यह कि अपीलकर्ता द्वारा कभी भी कोई अपराध नहीं किया गया था, जहां तक अभियोजक का संबंध था।

एफ. जाँच के समापन के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज ने खंड 164 के तहत अभियोजक द्वारा दिए गए बयान पर ध्यान देते हुए भा.दं.सं. सी. की खंड 376 और 342 के तहत अपराधों का संज्ञान नहीं लेने का आदेश पारित किया और न केवल अपीलकर्ता को बरी कर दिया, बल्कि जांच एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की।

जी. पीड़ित, लोक अभियोजक ने विद्वान सत्र न्यायाधीश, सिरोही के समक्ष एक

पुनरीक्षण दायर किया, जिसमें, उपरोक्त आदेश दिनांक आई. डी. 1 को दो आधारों पर उलट दिया गया था, पहला, कि भा.दं.सं. सी. की धारा 376 और 342 के तहत एक मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था और इसलिए मजिस्ट्रेट को अपीलकर्ता को किसी भी आधार पर आरोपमुक्त/बरी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि वह मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने के लिए बाध्य था, जो इस मुद्दे से निपटने के लिए एकमात्र सक्षम अदालत थी।दूसरा, अभियोजक का कथित बयान

खंड 164 Cr.P.C के तहत भरोसा करने लायक नहीं था क्योंकि उसे पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया था।एच. सत्र न्यायालय के दिनांक 1 के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अपने विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का रुख किया, दोनों मामलों में सत्र न्यायालय के आदेश की पुष्टि की।

इसलिए यह अपील की गई है।

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया है कि खंड 164 0 Cr.P.C के तहत दर्ज अभियोजक के बयान को देखते हुए, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज ने अपराध का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है और अपीलकर्ता को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि उक्त आदेश में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है, और इसलिए यह कहा गया है कि दोनों, पुनरीक्षण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी इसे उलटने में गंभीर त्रुटि की है।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अजय वीर सिंह जैन ने अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट को उक्त अपराधों का संज्ञान लेने से इनकार नहीं करना चाहिए था और अभियोजक के बयान पर ध्यान दें के बाद अपीलकर्ता को बरी करने में गंभीर त्रुटि की है, जो खंड 164 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था। उक्त बयान बहुत जल्दबाजी में दर्ज किया गया था।यह आगे प्रस्तुत किया

जाता है कि, चूंकि अभियोजक पुलिस की किसी भी सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुआ था, इसलिए खंड 164 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया उसका बयान स्वीकार करने योग्य नहीं है।इस प्रकार, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील खारिज की जा सकती है।

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

जोगेंद्र नाहक और अन्य अन्य मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ।उड़ीसा राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 2565 ने अभिनिर्धारित किया कि खंड 164 की उप-खंड 5, एक व्यक्ति के बयान से संबंधित है, जो एक अभियुक्त के बयान यानी एक स्वीकारोक्ति के अलावा है।इस तरह का बयान तभी दर्ज किया जा सकता है जब ऐसा बयान देने वाले व्यक्ति को पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसी कार्रवाई के मामले में, जिसमें ऐसे व्यक्ति को अपनी इच्छा से मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है, अनुमति दी जाती है, और अदालत के दरवाजे उनके लिए खुले होते हैं कि वे अपनी इच्छा के अनुसार आएं, और यदि मजिस्ट्रेट उनके सभी बयान दर्ज करना शुरू कर देता है, तो दोषियों द्वारा प्रायोजित बहुत से व्यक्ति उक्त दोषियों की सहायता के लिए अग्रिम रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट अदालतों के पोर्टल के सामने जमा हो सकते हैं।इस तरह के बयान अभियुक्त को जमानत और आरोपमुक्त करने के आदेश प्राप्त करने में बहुत मददगार होंगे।

6. उक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा महाबीर 9. बनाम हरियाणा राज्य, ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2503 में तथ्यों के आधार पर अलग किया गया था, लेकिन न्यायालय ने इस तथ्य पर अपनी पीड़ा व्यक्त की कि उक्त मामले में एक व्यक्ति का बयान मजिस्ट्रेट द्वारा खंड 164 Cr.P.C के तहत दर्ज किया गया था, उसे व्यक्तिगत

रूप से जाने बिना या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त व्यक्ति की पहचान करने का कोई प्रयास किए बिना।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ॥ स्पष्ट है कि यह मामला जोगेंद्र नाहक अन्य अन्य मामलों में तीन न्यायाधीशों की पीठ के उपरोक्त निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। (सुप्रा), जिसने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति को खंड 164 Cr.P.C के तहत उसका बयान दर्ज करने के लिए पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही, जिन्होंने आवेदन पर विचार किया अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज को अभियोजक का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, मामले में अभियोजक को ज्ञात नहीं था अन्य बाद वाले ने किसी भी अदालत के अधिकारी/वकील/पुलिस या किसी अन्य द्वारा पहचान के प्रयास के बिना उसका बयान भी दर्ज किया।

8. संजय गांधी बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 514 में, इस अदालत ने एक आरोपी को आरोपमुक्त करने के लिए मजिस्ट्रेट की क्षमता पर विचार करते हुए, तत्काल मामले जैसे मामले में, अभिनिर्धारित कियाः..... न्यायिक न्यायालय के लिए यह खुला नहीं है कि वह स्वयं को संतुष्ट करने की प्रक्रिया शुरू करे कि प्रथमदृष्टया मामला गुण-दोष के आधार पर बनाया गया है।पहले की संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र कभी उनके पास निहित था, लेकिन अब वर्तमान संहिता के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है।इसलिए, यह मानना कि वह प्रथमदृष्टया संतुष्टि के लिए भी गुण-दोष में जा सकते हैं, खंड 207-ए (पुरानी संहिता) को उसके वर्तमान गैर-विवेकाधीन आकार में फिर से ढालने के संसद के उद्देश्य को विफल करने के लिए है। अभियान का उद्देश्य इस परिवर्तन से था और यह सफलतापूर्वक पराजित हो जाएगा यदि हम व्याख्यात्मक रूप से मानते हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमे का एक ड्रेस रिहर्सल आदेश में है।हमारे विचार में, जिस संकीर्ण निरीक्षण छेद द्वारा से दोषी मजिस्ट्रेट को मामले को देखना है, वह उसे केवल यह पता लगाने के लिए सीमित करता है कि

क्या मामला, जैसा कि पुलिस रिपोर्ट द्वारा खुलासा किया गया है, मजिस्ट्रेट को केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध दिखाने के लिए प्रतीत होता है।पुलिस रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों को सही मानते हुए .मजिस्ट्रेट को केवल सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है।यदि गलती से दंड संहिता की कोई गलत खंड उद्धृत की जाती है, तो वह उस पहलू पर गौर कर सकता है।यदि पुलिस द्वारा किसी भी सामग्री द्वारा असमर्थित बनाए गए तथ्यों की सूचना दी जाती है और एक सत्र अपराध पेश किया जाता है, तो आरोपी को आरोपमुक्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 227 के तहत सत्र न्यायालय के लिए खुला है।यह प्रावधान अभियुक्त की कथित शिकायत का ध्यान रखता है।"(जोर दिया गया)

9. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि जब कोई अपराध सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञेय होता है, तो मजिस्ट्रेट मामले की जांच नहीं कर सकता है और आरोपी को आरोपमुक्त नहीं कर सकता है।अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद भी उसके लिए ऐसा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उसके पास मामले की जांच करने या देखने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

10. इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि मजिस्ट्रेट का अपीलकर्ता को आरोपमुक्त करने का कोई कार्य नहीं था।वास्तव में, पुराने Cr.P.C में खंड 207-ए ने मजिस्ट्रेट को इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया।हालाँकि, 1973 में उक्त खंड 207-ए के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है। वह कानून के तहत मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने के लिए बाध्य था, जहां आरोपमुक्त करने के लिए इस तरह के आवेदन पर विचार किया जाएगा।इसलिए, निर्वहन का आदेश एक शून्यता है, जो अधिकार क्षेत्र के बिना है।

11. इसके अलावा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव में साक्ष्य को ध्यान में रखने की अनुमति नहीं थी क्योंकि इस न्यायालय द्वारा

लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप तैयार करने के समय, केवल जिन दस्तावेजों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे आरोप-पत्र के साथ जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज हैं।जिस दस्तावेज पर आरोपी भरोसा करना चाहता है, उसे सबूत के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।यदि इस तरह के साक्ष्य पर विचार किया जाना है, तो आरोप तय करने के चरण में एक छोटा परीक्षण होगा।यह संहिता के उद्देश्य को विफल कर देगा।खंड 227 द्वारा अभिनिर्धारित अभियुक्त की प्रस्तुतियों को सुनने के प्रावधान का अर्थ है अभियोजन पक्ष द्वारा दायर मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर अभियुक्त की प्रस्तुतियों को सुनना और इससे अधिक कुछ नहीं। भले ही, एक दुर्लभ मामले में बचाव पक्ष के साक्ष्य पर विचार करने की अनुमति है, अगर ऐसी सामग्री आश्वस्त रूप से स्थापित करती है कि पूरा अभियोजन संस्करण पूरी तरह से हास्यास्पद तर्क, हास्यास्पद तर्क या मनगढ़ंत है, तो तत्काल मामला उस श्रेणी में नहीं आता है।

(वीडियोःउड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाधी, ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1512; उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्र नाथ पाधी, ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 359; एस. एम. एस. फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाम, ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3512; भारत पारिख बनाम सी. बी. आई. , (2008) 10 एस. सी. सी. 109; और रुक्मिणी नार्वेकर बनाम विजया सतार्देकर और अन्य, ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1013)

12. अदालत को संज्ञान नहीं लेने के पाठ्यक्रम का सहारा लेकर दोषमुक्ति का आदेश पारित नहीं करना चाहिए, जहां प्रथमदृष्टया मामला जांच एजेंसी द्वारा बनाया जाता है।इसके अलावा, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह पीड़ित के अधिकार और हितों की रक्षा करे, जो आरोपमुक्त करने की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है।खंड 227 के आवेदन के चरण में, अदालत को यह पता लगाने के लिए साक्ष्य को स्थानांतरित आदेशना पड़ता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। इस प्रकार, इस स्तर पर साक्ष्य की सराहना की अनुमति नहीं है।(वीडियोःपी. विजयन

बनाम केरा राज्य/ए और ए. एन. आर., ए. आई. आर 2010 एस. सी. 663; ए. आर. एस. मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1103)।

13. संहिता की योजना, विशेष रूप से, धारा 207 से 209 के प्रावधान, मजिस्ट्रेट को आरोप पत्र दायर होने पर मामले को सत्र न्यायालय को सौंपने का आदेश देती है। इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस द्वारा स्थापित मामले में विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले का समर्पण अनिवार्य है संहिता की योजना में केवल यह प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट यह निर्धारित कर सकता है कि क्या रिपोर्ट में बताए गए तथ्य सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारण योग्य अपराध बनाते हैं।एक बार जब वह इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि रिपोर्ट में आरोप लगाए गए तथ्य, विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य अपराध बनाते हैं, तो उसे मामले को सत्र न्यायालय को सौंपना चाहिए।

14. मजिस्ट्रेट, उदाहरण के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 190 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता, संज्ञान लेने से इनकार कर सकता है यदि अभिलेख पर सामग्री ऐसा वारंट करती है। मजिस्ट्रेट को, ऐसे मामले में, संतुष्ट होना चाहिए कि धारा 161 और 164 के तहत दर्ज शिकायत, केस डायरी, गवाहों के बयान, यदि कोई हो, तो कोई अपराध नहीं बनाते हैं। इस स्तर पर, मजिस्ट्रेट एक न्यायिक कार्य करता है। हालाँकि, वह अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना नहीं कर सकता है और इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि कौन सा साक्ष्य स्वीकार्य है, या उस पर भरोसा किया जा सकता है।इस प्रकार, इस स्तर पर साक्ष्य का मूल्यांकन अस्वीकार्य है।मजिस्ट्रेट मामले में साक्ष्य और संभावना के संतुलन को तौलने के लिए सक्षम नहीं है।

15. हम अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए निवेदन में कोई बल नहीं पाते हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज ने विभिन्न निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार सख्ती से कार्रवाई की है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से

अभिनिर्धारित किया गया है कि एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दायर किए जाने पर विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में भी कार्यवाही को छोड़ने की शक्ति है। उन्होंने मीनू कुमारी और अन्न बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।बिहार राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 1937, जिसमें इस न्यायालय ने भगवंत 9. बनाम पुलिस आयुक्त और ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1285 में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेने और कार्यवाही को छोड़ने का फैसला प्राथमिकीता है या यह विचार रखता है कि ए. आई. आर. में उल्लिखित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, सूचना देने वाले को नोटिस देना और मामले में सुनवाई की मंजूरी देना अनिवार्य हो जाता है।हाथ में मामले में, स्वीकार्य रूप से, मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही को छोड़ने से पहले शिकायतकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया है और इस प्रकार, कानून की अनिवार्य आवश्यकता का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है।

16. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष दायर आवेदन पर अभियोजक के साथ-साथ उसके वकील ने भी हस्ताक्षर किए हैं।हालाँकि, कथित अधिवक्ता या किसी और द्वारा अभियोजक की कोई पहचान नहीं की गई है।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही, अभियोजक की पहचान किए बिना आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े और इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि वह अभियोजक को व्यक्तिगत रूप से जानता था। वकील द्वारा उसकी पहचान किए जाने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज ने अभियोजक का बयान दर्ज किया।अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वह अपने माता-पिता या अपने किसी अन्य संबंधित व्यक्ति के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही या न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज के समक्ष पेश हुई थी।ऐसी परिस्थितियों में, इस प्रकार अभिलिखित कथन अपना महत्व और कानूनी पवित्रता खो देता है।

17. मामले के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही ने 9.4.1994 पर एक आदेश पारित किया।अभियोजक उसी तारीख को सिरोही से दूर एक स्थान पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज के समक्ष कागजात/आदेश आदि के साथ पेश हुआ और उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लोक अभियोजक को उसी तारीख को शाम 4 बजे केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया।इस प्रकार, इसे अगले दिन सुबह डी में पेश करने का निर्देश जारी किया गया था।बयान 10.4.1997 पर दर्ज किया गया था।तथ्य-स्थिति से पता चलता है कि अदालत बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ी और इतनी जल्दबाजी में की गई किसी भी कार्रवाई को मनमाना करार दिया जा सकता है।

18. मूल अभिलेख से पता चलता है कि अभियोजक ने स्वयं प्राथमिकी दर्ज की थी और उसी पर उसके हस्ताक्षर हैं।अगले दिन उसकी चिकित्सकीय जांच की गई और चिकित्सकीय रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर भी हैं।हमने उपरोक्त हस्ताक्षरों की तुलना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष खंड 164 के तहत उनका बयान दर्ज करने के लिए दायर आवेदन पर दिखाई देने वाले हस्ताक्षरों के साथ की है. साथ ही, खंड 164 के तहत उनके द्वारा कथित रूप से दिए गए बयान पर हस्ताक्षर के साथ, और उसी की जांच करने के बाद, प्रथमदृष्टया हमारा विचार है कि वे एक ही व्यक्ति द्वारा नहीं किए गए हैं, क्योंकि हस्ताक्षर के दो सेट मेल नहीं खाते हैं, बल्कि उनके बीच एक स्पष्ट असमानता है।

19. हस्ताक्षर की पहचान के साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (इसके बाद 'साक्ष्य अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की तीन धाराओं यानी धारा 45,47 और 73 द्वारा निपटाया गया है।उक्त अधिनियम की खंड 73 में न्यायालय द्वारा अपनी उपस्थिति में दिए गए लिखित नमूने के साथ की गई तुलना का प्रावधान है, या स्वीकार किया गया है, या संबंधित व्यक्ति का लेखन साबित हुआ है।(वीडियोः राम चंद्र और अन्र. वी.उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 381; ई. एस. मिश्रा अन्य मोहम्मद ईसा, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1728; शशि कुमार बनर्जी और

अन्य बनाम सुबोध कुमार बनर्जी, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 529; फखरुद्दीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1326; और महाराष्ट्र राज्य बनाम सुखदेव सिंह और ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 2100)।

20. मुरारी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 363 में, इस न्यायालय ने उक्त मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि यदि उपलब्ध लिखावट के संबंध में अदालत की सहायता करने के लिए कोई विशेषज्ञ राय नहीं है, तो अदालत को कुछ आधिकारिक पाठ्यपुस्तक और अदालत के अपने अनुभव और ज्ञान से मार्गदर्शन लेना चाहिए, हालांकि, इसके अभाव में भी, उसे किसी अन्य साक्ष्य के साथ या उसके बिना विशेषज्ञ के साथ या उसके बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए।

21. ए. नी/अलोहितदासन नादर बनाम जॉर्ज मास्क्रीन और अन्य, 1994 सप। (2) धारा 619, इस न्यायालय ने एक चुनाव विवाद से जुड़े मामले पर विचार किया कि क्या कुछ मतदाताओं ने एक से अधिक बार मतदान किया था।मतदाता सूची के काउंटर फॉयल पर उनके हस्ताक्षरों की तुलना उनके स्वीकृत हस्ताक्षरों से करना मुद्दा था।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चुनाव मामलों में जब मामले के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय हस्ताक्षरों की तुलना करने का कार्य अपने ऊपर लेता है, और इसलिए हस्ताक्षर विशेषज्ञ से तुलना करने के लिए उक्त हस्ताक्षर भेजने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।इस तरह का निर्णय लेते समय, न्यायालय द्वारा राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम पाली राम, ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 14; और राम प्यारेलाल श्रीवास्तव बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1523 में अपने पहले के फैसलों पर भरोसा रखा गया था।

22. ओ. भारतन बनाम के. सुधाकरन और अन्य, ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1140 में, इस न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया और कहा कि किसी मामले के तथ्य यह तय करने के लिए प्रासंगिक होंगे कि न्यायालय हस्ताक्षरों की

तुलना करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कहां करेगा और वह मामले को किसी विशेषज्ञ को कहां भेजेगा।न्यायालय की टिप्पणियां इस प्रकार हैंः

'हमारे विचार में विद्वान न्यायाधीश सही नहीं था... एक कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता के बिना भी विचाराधीन हस्ताक्षरों की वास्तविकता और प्रामाणिकता पर निर्णय लेने का खतरनाक कार्य अपने ऊपर लेना, जिसकी सेवाओं का आसानी से लाभ उठाया जा सकता था।लोक इच्छा के फैसले को रद्द करना समाज के लिए उतना ही गंभीर चिंता का विषय है जितना कि आपराधिक अपराधों से संबंधित कानूनों का प्रवर्तन, यदि अधिक नहीं है।यद्यपि विवादित हस्ताक्षरों की स्वीकृत हस्ताक्षरों के साथ वैज्ञानिक तुलना के बाद न्यायाधीश या जूरी के रूप में कार्य करना विशेषज्ञ का प्रांत है, लेकिन ऐसी स्थितियों में अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम के प्रति न्यायालय द्वारा दी गई सावधानी को अंतिम रूप से दिए गए निर्णय से उत्पन्न होने वाले गंभीर परिणामों की परवाह किए बिना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

(यह भी देखेंःला/इट पोपली बनाम केनरा बैंक और अन्य, ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1795; जगजीत 9. बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2006) 11 एस. सी. सी. 1; तिरुवेंगदा पिल्लई बनाम नवनीथमल, ए. आई. आर. 2008. एस. सी. 1541; और जी. सोमेश्वर राव बनाम समीनेनी नागेश्वर राव और अन्य, (2009) 14 धारा 677)।23.एक हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय किसी भी अन्य गवाह की तरह गलत/त्रुटि के लिए उत्तरदायी है, और फिर भी, इसे बेकार के रूप में दरकिनार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को हस्ताक्षर या लिखावट की तुलना करने से रोकने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है, विवादित लेखन की तुलना स्वीकृत लेखन से करने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करके और फिर उक्त लिखावट को समान या अलग साबित करने के लिए अपने स्वयं के अवलोकन को लागू करने से, जैसा भी मामला हो, लेकिन ऐसा करने में, न्यायालय स्वयं इस संबंध में विशेषज्ञ नहीं बन सकता है और उसे एक विशेषज्ञ की भूमिका निभाने से बचना चाहिए, इस सरल कारण से कि न्यायालय की

राय भी निर्णायक नहीं हो सकती है।इसलिए, जब न्यायालय ऐसा कार्य अपने ऊपर लेता है, और निष्कर्ष पूरी तरह से हस्ताक्षर या हस्तलेखन की तुलना के आधार पर दर्ज किए जाते हैं, तो न्यायालय को इसमें शामिल जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि न्यायालय द्वारा बनाई गई राय निर्णायक नहीं हो सकती है और त्रुटि के लिए अतिसंवेदनशील है, विशेष रूप से जब अभ्यास किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो विषय से परिचित नहीं है।इसलिए, न्यायालय को विवेक और सावधानी के मामले में अपने निष्कर्षों को केवल अपने द्वारा की गई तुलना पर आधारित करने में संकोच या देरी करनी चाहिए।हालाँकि, जहाँ किसी विशेषज्ञ या किसी गवाह की राय है, वहाँ न्यायालय अपने निर्णय को निर्णायक महत्व या प्रभाव प्रदान करने के लिए हस्ताक्षर, या लिखावट की तुलना करके अपने स्वयं के अवलोकन को लागू कर सकता है।24. उपरोक्त चर्चा निम्नलिखित निष्कर्षों की ओर ले जाती हैः

I. बलात्कार की घटना के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।Dy.S.P. ने अभियोजक का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने अपीलकर्ता के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाने वाले तथ्यों को सुनाया।

II. अभियोजक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष 9.4.1997 पर पेश हुआ और शिकायत दर्ज की, जिसमें कहा गया कि पुलिस मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही थी।उसने एक आवेदन दायर किया कि उसका बयान खंड 164 Cr.P.C के तहत दर्ज किया जाए।

III. अभियोजक ने उक्त आवेदन पर हस्ताक्षर किए थे।उस पर उनके वकील ने भी हस्ताक्षर किए थे।हालांकि, किसी ने उसकी पहचान नहीं की।

IV. यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि वह किसके साथ अदालत में पेश हुई थी।

V. प्राथमिकी आर. और चिकित्सा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर से, यह प्रतीत होता है कि वह एक शिक्षित व्यक्ति नहीं है और मुश्किल से अपने हस्ताक्षर बना सकती है।

VI. इस प्रकार, यह संदेह पैदा करता है कि कैसे एक 18 वर्षीय, जो एक अनपढ़ देहाती ग्रामीण है, अदालत में पहुंची और उसे कैसे पता था कि उसका बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जा सकता है।

VII. इसके अलावा, वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही के सामने पेश हुई, न कि शेओगंज में क्षेत्र मजिस्ट्रेट के सामने।

VIII. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसी दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज को उनका बयान दर्ज करने का निर्देश देते हुए आवेदन का निपटारा कर दिया।

IX. अभियोजक सिरोही से बहुत दूर न्यायिक सी मजिस्ट्रेट, शेओगंज के समक्ष पेश हुआ, जहाँ वह मूल रूप से गई थी, और खंड 164 Cr.P.C के तहत उसका बयान 9.4.1997 पर दर्ज किया गया था, क्योंकि लोक अभियोजक केसडायरी को पेश नहीं कर सका था।

x. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही और न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज के समक्ष दस्तावेजों पर अभियोजक के हस्ताक्षर, प्राथमिकी और चिकित्सा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं।इनके बीच स्पष्ट अंतर है, जो संदेह पैदा करता है।

XI. जाँच पूरा करने के बाद, 20.3.1998 पर न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज के समक्ष आरोप-पत्र दायर किया गया था।

XII न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज ने दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से, खंड 164 के तहत दर्ज अभियोजक के बयान के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि अदालत ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लेने में गलती की क्योंकि उक्त बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

XIII पुनरीक्षण अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया है कि खंड 164 Cr.P.C के तहत बयान सही ढंग से दर्ज नहीं किया गया था।उक्त अदालतों ने अपराध का संज्ञान नहीं लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज, दिनांक 1 के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया है।

XIV पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 207-ए के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज को मामले को सत्र अदालत को सौंप देना चाहिए था क्योंकि उक्त आवेदन केवल सत्र अदालत द्वारा दायर किया जा सकता था।इसके अलावा, अदालत के लिए उस स्तर पर बचाव पक्ष के साक्ष्य के भार की जांच करने की अनुमति नहीं थी।इस प्रकार, यह आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना महत्वहीन और महत्वहीन है।

25. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपील में कोई बल नहीं पाते हैं। तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है। पुनरीक्षण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को बरकरार रखा जाता है।मूल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट, शेओगंज द्वारा 23.4.2012 पर सत्र न्यायालय को सौंपा गया है। सत्र न्यायालय से अनुरोध है कि वह कानून के अनुसार सख्ती से आगे बढ़े और बिना किसी और देरी के मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाए।हम यह स्पष्ट करते हैं कि इसमें की गई कोई भी टिप्पणी किसी भी पक्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि वे केवल वर्तमान मामले का फैसला करने के लिए की गई हैं।

के. के. टी. अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।